



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 333]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 22, 2010/पौष 1, 1932

No. 333]

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 22, 2010/PAUSHA 1, 1932

वित्त मंत्रालय

(ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 दिसम्बर, 2010

सं. 3946.—बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 (1980 का 40) की धारा 12 की उप-धारा (2) के साथ पठित धारा (19) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श और केन्द्रीय सरकार की पूर्वमंजूरी से ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन विनियमों को ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियम, 2010 कहा जाएगा।
- (2) ये विनियम संबंधित विनियमों में कहीं भी अन्यथा वर्णित को छोड़कर जून, 2005 के दूसरे दिन से लागू होंगे।
2. ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में (यहां आगे उक्त विनियम कहा गया है) विनियम 3 में,—

(i) खण्ड (छ) के लिए निम्नलिखित खण्ड को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

(छ) “परिवार” से अभिप्रेत है अधिकारी की पत्नी या पति (जो बैंक की कर्मचारी नहीं है), पूर्णतया आश्रित अविवाहित बच्चे (आश्रित सौतेले तथा कानूनी रूप से दत्तक लिए गए बच्चे) और सामान्यतया साथ रह रहे तथा अधिकारी पर पूर्णतः आश्रित माता-पिता

(ii) निम्नलिखित उप-खण्ड (त) को जोड़ा जाए, अर्थात् :

(त) पूर्णतः आश्रित बच्चों या माता-पिता से अभिप्रेत है बच्चे या माता-पिता जिनकी आय 2550 रु. प्रतिमाह से अधिक नहीं है।

टिप्पणी : यदि माता-पिता में से किसी एक की आय 2550 रु. प्रतिमाह से अधिक हो जाती है या माता-पिता दोनों की कुल आय 2550 रु. प्रतिमाह से अधिक हो जाती है, माता-पिता दोनों को कर्मचारी पर पूर्णतः आश्रित नहीं माना जाएगा।

3. उक्त विनियमों में, विनियम 4 में, उप विनियम (4) के लिए निम्नलिखित उप विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

(4) 1 नवम्बर, 2002 को तथा इस तारीख से प्रत्येक श्रेणी के सामने विनिर्दिष्ट वेतनमान निम्नानुसार होंगे :-

(क) सर्वोच्च कार्यपालक श्रेणी

वेतनमान - VII - 29340-680/2-30700-900/1-31600-1000/1-32600 रु.

वेतनमान - VI - 26620-680/4-29340 रु.

(ख) वरिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी

वेतनमान - V - 24140-620/4-26620 रु.

वेतनमान - IV - 20480-560/1-21040-620/5-24140 रु.

(ग) मध्यम प्रबन्धन श्रेणी

वेतनमान - III - 18240-560/5-21040-620/2-22280 रु.

वेतनमान - II - 13820-500/1-14320-560/10-19920 रु.

(घ) कनिष्ठ प्रबन्धन श्रेणी

वेतनमान - I - 10000-470/6-12820-500/3-14320-560/7-18240 रु.

टिप्पणी : प्रत्येक अधिकारी जो 31 अक्टूबर, 2002 को लागू वेतनमान द्वारा शासित है, को 1 नवम्बर, 2002 के अनुसार इस विनियम में निश्चित किए गए वेतनमान में चरण-दर-चरण आधार पर अर्थात् संबंधित वेतनमानों में पहले चरण के बाद तदनुसूची चरणों पर नियत किया जाएगा तथा वेतनवृद्धियां अन्यथा की गई व्यवस्थाओं को छोड़कर, सामान्यतया वार्षिक तारीख को देय होगी।

(4क) उप विनियम (1), (2), (3) और (4) की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि बैंक को हर समय इन सभी श्रेणियों में अधिकारियों को रखना अपेक्षित है।

4. उक्त विनियमों में, विनियम 5 के लिए निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात्

5. वेतनवृद्धियां

(1) विनियम 4 के उप-विनियम (4) के प्रावधानों के अध्ययन 1 नवम्बर, 2002 को तथा से वेतनवृद्धियां निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जाएगी अर्थात् :

(क) विनियम 4 के उप विनियम(4) में उप-वर्णित विभिन्न वेतनमानों में विनिर्दिष्ट वेतनवृद्धियाँ सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी के अध्ययधीन वार्षिक आधार पर प्रोदभूत होंगी और वे उस महीने की पहली तारीख को दी जाएगी जिस महीने में देय होती हैं।

(ख) वेतनमान I और वेतनमान II के अधिकारियों को अपने संबंधित वेतनमानों के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष के बाद अगले उच्चतर वेतनमान में अवरोध वेतनवृद्धि (याँ) सहित आगे की वेतनवृद्धियाँ केवल नीचे (ग) में वर्णित आधार पर सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार दी जाएंगी, बशर्ते कि वे दक्षता अवरोध को पार कर लें।

(ग) ऊपर (ख) में उल्लिखित अधिकारियों सहित मध्यम प्रबन्धन ग्रेड वेतनमान I और वेतनमान III के अधिकतम पर पहुंचने वाले अधिकारियों को यथा स्थिति, वेतनमान II और वेतनमान III की अंतिम स्टेज पर पहुंचने के बाद प्रत्येक 3 वर्षों की सेवा पूरी होने पर अवरोध वेतनवृद्धि (याँ) दी जाएगी। वेतनमान II की अंतिम स्टेज पर पहुंच चुके अधिकारियों के मामले में 500/-रु. की अधिक से अधिक दो वेतनवृद्धियाँ दी जाएगी और वेतनमान III की अंतिम स्टेज पर पहुंचने वाले अधिकारियों के मामले में 620/-रु. की एक वेतनवृद्धि दी जाएगी।

परन्तु 01.11.1994 और उसके बाद मूल वेतनमान III के अधिकारी अर्थात् जो वेतनमान III में भर्ती या पदोन्नत हुए हैं, पहली अवरोध वेतनवृद्धि पाने के तीन वर्ष पश्चात् दूसरी अवरोध वेतनवृद्धि प्राप्त करने के पात्र होंगे।

परन्तु अगले उच्चतर वेतनमान में ऐसी वेतनवृद्धि (याँ)/अवरोध वेतनवृद्धि (याँ) उस अधिकारी को नहीं दी जाएगी जिसने पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर दिया हो।

टिप्पणी :

अगले उच्चतर वेतनमान में दी गई ऐसी वेतनवृद्धियों को पदोन्नति नहीं माना जाएगा। ऐसी वेतनवृद्धियाँ पाने के पश्चात् भी अधिकारी को, यथास्थिति, उसके अपने मूल पद के वेतनमान I और II के ही विशेषाधिकार, परिलब्धियाँ, ड्यूटी, उत्तरदायित्व अथवा पद मिलते रहेंगे।

(2) भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट का भाग I/भारतीय बैंकिंग व वित्त संस्थान का जूनियर एसोसिएट और भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर वेतनमान में एक अतिरिक्त वेतनवृद्धि दी जाएगी।

स्पष्टीकरण :

(क) जिस अधिकारी ने नियत तारीख से पहले अधिकारी के रूप में भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणपत्रित (सी ए आई आई बी) परीक्षा का भाग I और II उत्तीर्ण कर लिया हो, उसे नियत तारीख से यथास्थिति, अतिरिक्त वेतनवृद्धि अथवा वेतनवृद्धियाँ दी जाएगी बशर्ते कि उसने उक्त परीक्षा के दोनों भाग उत्तीर्ण करने पर कोई वेतनवृद्धि न ली हो अथवा केवल एक वेतनवृद्धि ली हो।

(ख) 1 नवम्बर, 1987 को और से, जो अधिकारी वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुँच गए हैं व पदोन्नति के अतिरिक्त आगे नहीं बढ़ सकते उन्हें सरकारी दिशानिर्देशों, यदि कोई हों, के आधार पर नीचे दी गई तालिका के अनुसार अतिरिक्त वेतनवृद्धि के बदले व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्रदान किया जाए :-

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट्स का केवल भाग I उत्तीर्ण किया हो	(i)	एक वर्ष के पश्चात् 100 रुपये प्रतिमाह जिसमें से 75 अधिवर्षिता लाभ के लिए होंगे
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i)	एक वर्ष के पश्चात् 100 रुपये प्रतिमाह जिसमें से 75 अधिवर्षिता लाभ के लिए होंगे
	(ii)	दो वर्ष के पश्चात् 250 रुपये प्रतिमाह जिसमें से 200 रुपये अधिवर्षिता लाभ के लिए होंगे

(ग) 1 नवम्बर, 1994 को, और से, अन्य बातें समान होने पर व्यावसायिक योग्यता भत्ते की मात्रा नीचे दी गई तालिका के अनुसार संशोधित होगी।

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट्स का केवल भाग I उत्तीर्ण किया हो	(i)	वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् 120 रुपये प्रतिमाह
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i)	वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुँचने के एक वर्ष पश्चात् 120 रुपये प्रतिमाह
	(ii)	वेतनमान की अधिकतम सीमा पर पहुँचने के दो वर्ष बाद 300 रुपये प्रतिमाह

बशर्ते जो अधिकारी विनियम 5 के उप विनियम (3) के उपबंध (ख) के अनुसार नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त करने के पात्र हैं वे यथास्थिति भाग IV भाग II के लिए ऐसा नियत वैयक्तिक भत्ता मिलने के एक वर्ष/2 वर्ष के उपरांत व्यावसायिक योग्यता भत्ता प्राप्त करेंगे।

(घ) 1 नवम्बर, 1999 को और से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट के अनुसार संशोधित होगी :-

तालिका

जिन्होंने केवल भारतीय बैंकर संस्थान की जूनियर एसोसिएट्स या सर्टिफाईड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स का भाग I उत्तीर्ण किया हो	(i)	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद 150 रु. प्रतिमाह
जिन्होंने जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स तथा सर्टिफाईड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स अथवा सर्टिफाईड एसोसिएट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हों	(i)	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद 150 रु. प्रतिमाह
	(ii)	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुँचने के एक वर्ष बाद 360 रु. प्रतिमाह

परन्तु, जो अधिकारी वेतनमान I और वेतनमान II में हैं और जिन्हें उप-विनियम (1) के खंड (ख) के अनुसार अगले उच्चतर वेतनमान में आगे वेतनवृद्धियां दी गई हैं, उन्हें यथास्थिति व्यावसायिक योग्यता वेतन ऐसे उच्चतर वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक अथवा दो वर्ष बाद, जैसा भी मामला हो, प्राप्त होगा।

(ड) 1 नवम्बर, 2002 को और से, अन्य बातें समान होने पर, व्यावसायिक योग्यता वेतन की राशि नीचे तालिका में विनिर्दिष्ट के अनुसार संशोधित होगी :-

तालिका

जिन्होंने भारतीय बैंकर्स संस्थान की जूनियर एसोसिएट अथवा भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट का भाग I उत्तीर्ण किया है	(i)	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद 300 रु. प्रतिमाह
जिन्होंने भारतीय बैंकर संस्थान की प्रमाणित एसोसिएट्स के दोनों भाग उत्तीर्ण किए हैं	(i)	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के एक वर्ष बाद 300 रु. प्रतिमाह
	(ii)	वेतनमान के अधिकतम स्तर पर पहुंचने के दो वर्ष बाद 750 रु. प्रतिमाह

परन्तु, जो अधिकारी वेतनमान I और II में हैं और जिन्हें उप-विनियम (1) के खंड (ख) में यथाविनिर्दिष्ट अगले उच्चतर वेतनमान में आगे वेतनवृद्धियां दी गई हैं, उन्हें व्यावसायिक योग्यता वेतन ऐसे उच्चतर वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक अथवा दो वर्ष बाद जैसा भी मामला हो, प्राप्त होगा।

टिप्पणी :

- (i) यदि किसी अधिकारी को जिसे व्यावसायिक योग्यता वेतन मिल रहा है, अगले उच्चतर वेतनमान में पदोन्नत किया जाता है तो ऐसे उच्चतर वेतनमान में उसका वेतन निर्धारित करते समय उसे वेतनमान में उपलब्ध वेतनवृद्धियों की सीमा तक जूनियर एसोसिएट आफ इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बैंकर्स /सर्टिफाइड एसोसिएट ऑफ इंडियन बैंकर्स परीक्षा उत्तीर्ण करने पर अतिरिक्त वेतनवृद्धियां दी जाएगी और यदि वेतनमान में कोई वेतनवृद्धियां उपलब्ध नहीं हैं, तो अधिकारी वेतनवृद्धि (यों) के स्थान पर व्यावसायिक योग्यता वेतन पाने का पात्र होगा।
- (ii) 1 नवम्बर, 1994 को या से, व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन को यथास्थिति मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता तथा अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।
- (iii) कोई अधिकारी यदि पदोन्नति का प्रस्ताव मिलने पर उसे अस्वीकार कर देता है तो वह उपरोक्तानुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन पाने का पात्र नहीं होगा।
- (iv) यदि कोई अधिकारी अधिकतम वेतनमान पर पहुंचने के बाद भारतीय बैंकर्स संस्थान के प्रमाणित एसोसिएट आफ बैंकर्स या भारतीय बैंकर्स संस्थान का प्रमाणित एसोसिएट (एक या दोनों भाग) योग्यता प्राप्त कर लेता है तो ऐसी योग्यता प्राप्त करने की तारीख से व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त दी जाएगी और व्यावसायिक योग्यता वेतन की अगली किस्तें व्यावसायिक योग्यता वेतन की पहली किस्त जारी करने की तारीख के अनुसार होगी।
- (v) यदि किसी अधिकारी ने 2 जून, 2005 को खंड (iv) में संदर्भित कोई उक्त योग्यताएं पहले ही अर्जित कर ली हों और ऐसी योग्यता/योग्यताएं प्राप्त करने पर कोई वेतनवृद्धि या व्यावसायिक योग्यता वेतन अर्जित नहीं किया हो तो उसे 1 नवम्बर, 2002 से या ऐसी योग्यता/योग्यताएं अर्जित करने की तारीख से, जो भी बाद में हो, यहां की गई व्यवस्था के अनुसार व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी किया जाएगा।

(3) (क) जो अधिकारी 1 नवम्बर, 1993 को बैंक की स्थायी सेवा में हैं उन्हें वेतनमान में एक अग्रिम वेतनवृद्धि दी जाएगी। जो अधिकारी 1 नवम्बर, 1993 को परीवीक्षा पर हैं उन्हें एक अग्रिम वेतनवृद्धि स्थायीकरण के एक वर्ष पश्चात् दी जाएगी।

टिप्पणी :-

अग्रिम वेतनवृद्धि के कारण वार्षिक वेतनवृद्धि की तारीख में कोई परिवर्तन नहीं होगा ।

- (ख) जो अधिकारी वेतनमान के अधिकतम पर पहुंच चुका है या जो 01.11.1993 को अवरोध वेतनवृद्धि (याँ) प्राप्त कर चुका है, वह नवम्बर, 1993 के पहले दिन से नियत वैयक्तिक भत्ता प्राप्त कर सकेगा जो अंतिम आहरित वेतनवृद्धि और उस पर 01.11.1993 को देय मंहगाई भत्ता, तथा विनियम 22 के अनुसार लागू दरों पर मकान किराया भत्ता तथा नियत वैयक्तिक भत्ता मकान किराए भत्ते सहित यदि कोई हो, के बराबर होगा वयहां नीचे तालिका में यथाविनिर्दिष्ट होगा व अगला संशोधन होने तक वैध रहेगा ।

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	01.11.1993 को वेतनवृद्धि घटक पर मंहगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (ग) 1 नवम्बर, 1999 को तथा उसके बाद से, अन्य बातें समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन मकान किराया भत्ता सहित, यदि कोई हो, निम्नानुसार होगा :-

वेतनवृद्धि घटक	01.11.1997 को वेतनवृद्धि घटक पर मंहगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक भत्ता
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (घ) 1 नवम्बर, 2004 को और उसके बाद से अन्य बातों के समान होने पर, नियत वैयक्तिक वेतन मकान किराया भत्ता सहित, यदि कोई हो, नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगा और सेवा की पूरी अवधि हेतु अवरूद्ध रहेगा :-

तालिका

वेतनवृद्धि घटक	वेतनवृद्धि घटक पर 01.11.2002 के अनुसार मंहगाई भत्ता	जहां बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है वहां देय कुल नियत वैयक्तिक वेतन
(क) रु.	(ख) रु.	(ग) रु.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

टिप्पणी :-

(i) विनियम (5) के उप विनियम (3) के उप खंड (ख), (ग) और (घ) में तालिका के कॉलम (ग) के अंतर्गत निर्दिष्ट नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उन अधिकारियों को देय होगा जिन्हें बैंक का आवास उपलब्ध कराया गया है।

(ii) मकान किराये भत्ते के पात्र अधिकारियों को नियत वैयक्तिक भत्ता/नियत वैयक्तिक वेतन उनके द्वारा विनियम (4) के उप विनियम (2) तथा (3) में निर्दिष्ट अनुसार वेतनमान की अंतिम वेतनवृद्धि प्राप्त कर लेने पर (क) + (ख) + संबंधित अधिकारी द्वारा आहरित मकान किराया भत्ता होगा।

(iii) 1 नवम्बर, 1999 को तथा उसके बाद से नियत वैयक्तिक वेतन जारी करने से संबंधित उप विनियम (2) के स्पष्टीकरण (ग) में व्यावसायिक योग्यता वेतन जारी करने संबंधित अवधि में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

परन्तु यदि व्यावसायिक योग्यता वेतन की कोई किस्त, पिछले प्रावधानों के कारण एक वर्ष आगे कर दी गई है और 1 नवम्बर, 1999 को या बाद में देने हेतु नियत की गई है, तो वह अधिकारी को इस तारीख को और इसके बाद से जारी की जाएगी तथा वैयक्तिक योग्यता वेतन की दूसरी किस्त यदि कोई हो, 1 नवम्बर, 2000 को जारी की जाएगी।

(iv) नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन के वेतनवृद्धि घटक को अधिवर्षिता लाभों के लिए गिना जाएगा।

(ड) जिस अधिकारी को उपरोक्त उपखंड (क) के अनुसार एक अग्रिम वेतनवृद्धि मिल चुकी है, उसे ऊपर (ख), (ग) या (घ) में उल्लिखित नियत वैयक्तिक भत्ते/नियत वैयक्तिक वेतन की मात्रा वेतनमान के अधिकतम पर पहुंचने के एक वर्ष बाद प्राप्त होगी।

5. उपरोक्त विनियमों में, विनियम 21 में उप-विनियम (3) के बाद निम्नलिखित उप-विनियम को जोड़ा जाएगा अर्थात् :-

(4) 1 नवम्बर, 2002 को तथा उसके बाद मंहगाई भत्ता योजना निम्नानुसार होगी :-

(क) मंहगाई भत्ता अखिल भारतीय औसत श्रमिक वर्ग उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सामान्य) आधार 1960-100 की तिमाही औसत में 2288 अंकों के ऊपर 4 अंकों की प्रत्येक गिरावट या वृद्धि के हिसाब से देय होगा।

(ख) 1 नवम्बर, 2002 से जनवरी, 2005 के 31वें दिन तक की अवधि के दौरान मंहगाई भत्ता निम्नलिखित दरों के अनुसार देय होगा :-

- (i) 9650/-रु. तक जमा 'वेतन' का 0.18%
- (ii) 9650/-रु. से अधिक और 15350/-रु. तक जमा 'वेतन' का 0.15%
- (iii) 15350/-रु. से अधिक तथा 16350/-रु. तक जमा 'वेतन' का 0.9%
- (iv) 16350/-रु. से अधिक वेतन का 0.04%

(ग) 1 फरवरी, 2005 को तथा उसके बाद से मंहगाई भत्ता वेतन के 0.18% से देय होगा ।

टिप्पणी :-

- (क) मंहगाई भत्ते के प्रयोजन हेतु 'वेतन' से मूल वेतन तथा अवरोध वेतनवृद्धियां अभिप्रेत है ।
- (ख) मंहगाई भत्ते के लिए व्यावसायिक योग्यता भत्ते या व्यावसायिक योग्यता वेतन को विनियम 5 के उप-विनियम (2) में दिए गए स्पष्टीकरण (ग), (घ) और (ङ) के अनुसार गिना जाएगा ।

6. उक्त विनियमों में, विनियम 22 के लिए निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित होगा अर्थात् :-

22. मकान किराया भत्ता

- (1) (क) 1 नवम्बर, 1999 को या उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसकी पहली स्टेज के मूल वेतन के 2.5% के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा ।
- (ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा कोई आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह 1 नवम्बर, 1999 से या उसके बाद से नीचे दी गई तालिका के बराबर मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा अर्थात् :-

तालिका

कार्यस्थल निम्न स्थानों पर होने पर		देय मकान किराया भत्ता
(1)		(2)
(i)	सरकार के मार्गनिर्देशों के अनुसार समय-समय पर विनिर्दिष्ट प्रमुख 'क' वर्ग के नगर तथा समूह 'क' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 9% प्रतिमाह
(ii)	क्षेत्र I और समूह 'ख' के परियोजना क्षेत्र केन्द्रों में स्थानों पर	वेतन का 8% प्रतिमाह
(iii)	क्षेत्र II अर्थात् सभी स्थानों पर जो उपरोक्त (i) (ii) में कवर नहीं किए गए	वेतन का 7% प्रतिमाह

परन्तु, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान की पहली स्टेज के 2.5% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिए गए वास्तविक किराया या ऊपर कॉलम (2) के अनुसार देय मकान किराये भत्ते का 150% जो भी कम हो, होगा ।

- (2) (क) 1 नवम्बर, 2002 को या उसके बाद से यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की जाती है तो वह जिस वेतनमान में है उसकी पहली स्टेज के मूल वेतन के 0.5% के बराबर राशि या आवास हेतु मानक किराया, इनमें से जो भी कम हो, वसूल किया जाएगा।
- (ख) यदि किसी अधिकारी को बैंक द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान नहीं की जाती है तो वह 1 नवम्बर, 2002 को या उसके बाद से नीचे दी गई तालिका के अनुसार मकान किराया भत्ता पाने का पात्र होगा अर्थात् :-

तालिका

कार्यस्थल निम्न स्थानों पर होने पर		देय मकान किराया भत्ता
(1)		(2)
(i)	प्रमुख 'क' वर्ग के नगर तथा समूह 'क' के परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 8.5%
(ii)	क्षेत्र I में अन्य स्थान तथा वर्ग 'ख' में परियोजना क्षेत्र केन्द्र	वेतन का 7.5%
(iii)	अन्य स्थान	वेतन का 6.5%

परन्तु, यदि कोई अधिकारी किराये की रसीद प्रस्तुत करता है तो उसे देय मकान किराया भत्ता, जिस वेतनमान में वह है उस वेतनमान की पहली स्टेज के 2.5% से ऊपर, उसके द्वारा अपने आवास के लिए दिए गए वास्तविक किराया या ऊपर कॉलम (2) के अनुसार देय मकान किराये भत्ते का 150% जो भी कम हो, होगा।

3. यदि अधिकारी अपने मकान में रहता है तो वह उप-विनियम (1) के उपखंड (ख) और उप-विनियम (2) के उपखंड (ख) के परन्तुक में यथा उल्लिखित के आधार पर मकान किराया भत्ता पाने का हकदार होगा मानों वह नीचे (क) या (ख) में से अधिक वाले के बारहवें हिस्से के बराबर राशि मासिक किराये के रूप में अदा कर रहा हो :-

(क)

इनका कुल योग

- (i) उस मकान के लिए दिए जाने वाला पालिका कर; और
- (ii) भूमि की लागत सहित मकान की पूंजीगत लागत का 12% और यदि यह मकान किसी भवन का एक हिस्सा हो तो उस मकान के लिए लगने वाली भूमि की पूंजीगत लागत का समानुपातिक अंश विशेष फिक्सचर जैसे एयर कंडीशनर की लागत को छोड़कर, या

(ख)

मकान के पालिका कर निर्धारण के लिए लगाया गया वार्षिक मूल्य।

स्पष्टीकरण :-

- (1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए 'मानक किराए' का अर्थ है :-

- (क) यदि कोई मकान बैंक के स्वामित्व में हो तो मानक किराए का परिकलन सरकार द्वारा परिकलन की प्रचलित पद्धति के अनुसार किया जाएगा ।
- (ख) जहां मकान बैंक द्वारा किराये पर लिया गया हो, बैंक द्वारा देय सविदागत किराया अथवा ऊपर (क) में दर्शाई गई पद्धति के अनुसार परिकलित किराया, जो भी कम हो ।
- (2) मकान किराया भत्ते के प्रयोजन के लिए वेतन का तात्पर्य अवरोध वेतनवृद्धियों सहित मूल वेतन होगा ।
- (3) व्यावसायिक योग्यता भत्ता या व्यावसायिक योग्यता वेतन, जैसा भी मामला हो, को आवास किराये भत्ते के लिए 1 नवम्बर, 1994 से गिना जाएगा ।
- (4) इस विनियम के उप विनियम (1) और (2) तथा विनियम 23 के प्रयोजन के लिए क्षेत्र (I) और क्षेत्र (II) का अर्थ निम्नानुसार होगा ।

क्षेत्र I 12 लाख से अधिक जनसंख्या वाले स्थान
क्षेत्र II क्षेत्र I के अलावा सभी स्थान

7. उपरोक्त विनियमों में, विनियम 23 के लिए, निम्नलिखित विनियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

23. अन्य भत्ते

- (1) 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अधिकारी नीचे दी गई तालिका में दिए अनुसार नगर प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा :-

तालिका

	स्थान	दर
	(1)	(2)
(क)	क्षेत्र I के स्थान और गोवा राज्य	मूल वेतन का 4% अधिकतम 540 रु. प्रतिमाह
(ख)	5 लाख और उससे अधिक की जनसंख्या वाले स्थान और राज्य की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी एवं पोर्ट ब्लेयर, जो ऊपर (क) में नहीं आते	मूल वेतन का 3% अधिकतम 375 रु. प्रतिमाह
(ग)	अन्य स्थान	शून्य

- (2) 1 नवम्बर, 2002 से विशेष क्षेत्र भत्ते की दरें इन विनियमों की अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होंगी ।
- (3) 1 नवम्बर, 2002 को यदि अधिकारी ऐसे क्षेत्र में कार्य कर रहा हो जिसे समूह 'क' या समूह 'ख' के अंतर्गत आने वाले परियोजना क्षेत्र के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया हो तो वह समूह 'क' या समूह 'ख' के रूप में क्षेत्र के वर्गीकरण के अनुसार 210 रु. प्रतिमाह या 185 रु. प्रतिमाह की दर से परियोजना क्षेत्र प्रतिकर भत्ता पाने का पात्र होगा ।
- (4) 1 जनवरी, 2004 से यदि किसी अधिकारी को शैक्षिक वर्ष के बीच में एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित किया जाता है और यदि उसके एक या उससे अधिक बच्चे पहले स्थान पर स्कूल या कालेज

में पढ़ते हैं तो वह बाद वाले स्थान पर रिपोर्ट करने की तारीख से शैक्षिक वर्ष के अंत तक पढ़ रहे सभी बच्चों के लिए 500 रु. प्रतिमाह की दर से मध्य शैक्षिक स्थानांतरण भत्ता पाने का पात्र होगा ।

परन्तु यदि सभी बच्चे पहले वाले स्थान पर पढ़ाई बंद कर देते हैं तो यह भत्ता नहीं मिलेगा ।

- (5) 1 जून, 2005 को और उसके बाद से, यदि किसी अधिकारी को बैंक से बाहर सेवा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है तो वह उस पद से जुड़ी परिलब्धियाँ पाने का विकल्प दे सकता है जिस पर उसे प्रतिनियुक्त किया गया हो अथवा वह अपने वेतन के अतिरिक्त वेतन के 7.75% किंतु अधिकतम 1500/-रु. प्रतिमाह का प्रतिनियुक्ति भत्ता तथा ऐसे अन्य भत्ते ले सकता है जो उसे तब मिलते जब वह उस स्थान पर बैंक की सेवा में तैनात किया गया हो ।

परन्तु, यदि उसे ऐसे संगठन में प्रतिनियुक्त किया जाए जो उसी स्थान पर स्थित है, जहाँ प्रतिनियुक्ति से फौरन पहले वह तैनात था तो उसे उसके वेतन के 4% के बराबर किंतु अधिकतम 750/-रु. प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता मिलेगा ।

परन्तु, यदि अधिकारी को बैंक के प्रशिक्षण संस्थान में संकाय सदस्य के रूप में प्रतिनियुक्त किया जाए, तो वह अपने मूल वेतन के 4% के बराबर परन्तु अधिकतम 750/-रु. प्रतिमाह प्रतिनियुक्ति भत्ता पाने का हकदार होगा ।

- (6) यदि किसी अधिकारी से एक बार कम से कम 7 दिन की निरन्तर अवधि के लिए या किसी एक कलैण्डर माह में कुल 7 दिन किसी उच्चतर श्रेणी के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करवाया जाए, तो उसे उस अवधि के लिए, जिसमें उसने स्थानापन्न रूप से कार्य किया हो, यथानुपात उसके वेतनमान के 6% के बराबर भत्ता मिलेगा । स्थानापन्न भत्ते को केवल पेंशन/भविष्य निधि के प्रयोजन के लिए वेतन माना जाएगा ।

परन्तु, यदि कोई अधिकारी विनियम 6 के अंतर्गत केवल पदों के वर्गीकरण के पुनरीक्षण के परिणामस्वरूप किसी उच्चतर ग्रेड में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए आता है तो जिस तारीख को वर्गीकरण का पुनरीक्षण किया जाएगा उस तारीख से एक वर्ष की अवधि तक वह स्थानापन्न भत्ता पाने का हकदार होगा ।

- (7) यदि कोई अधिकारी ऐसी शाखा में तैनात है जहाँ बहियों को 1 अप्रैल और 30 सितम्बर को बन्द किया जाता है, वहाँ प्रत्येक लेखाबंदी के लिए 250/-रु. का लेखाबंदी भत्ता ।
- (8) 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से, यदि दिन के दौरान कार्यसमय दो भागों में बंटा हुआ है और कार्यसमय के इस विभाजन में कम से कम दो घंटे का अंतराल है तो अधिकारी, 125/-रु. प्रतिमाह की दर से विभाजित कार्यसमय भत्ता पाने का पात्र होगा ।
- (9) यदि किसी अधिकारी को छुट्टी के दिन किसी वॉल्ट या लॉकर के अभिरक्षक के रूप में कार्य करना पड़ता है तो जिस दर का वह हकदार हो उस दर पर दैनिक भत्ता पाने का पात्र होगा ।
- (10) नवम्बर, 2002 के पहले दिन और उसके बाद से, कोई अधिकारी नीचे दी गई उल्लिखित दर पर पहाड़ और ईंधन भत्ता पाने का पात्र होगा अर्थात् :

तालिका

	स्थान	दर
	(1)	(2)
(i)	3000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले स्थान	वेतन का 5% अधिकतम 1150 रु. प्रतिमाह
(ii)	1500 मीटर और अधिक परन्तु 3000 मीटर से कम ऊंचाई वाले स्थान	मूल वेतन का 2.5% अधिकतम 500 रु. प्रतिमाह
(iii)	1000 मीटर और उससे अधिक परन्तु 1500 मीटर से कम की ऊंचाई वाले स्थान और मरकारा टाऊन	मूल वेतन का 2% अधिकतम 400 रु. प्रतिमाह

टिप्पणी :-

(क) ऐसे स्थानों, जो कम से कम 750 मीटर ऊंचाई पर स्थित हैं और अधिक ऊंचाई वाले पहाड़ों से घिरे हैं जहां पर 1000 मीटर या अधिक की ऊंचाई को पार किए बिना पहुंचना संभव न हो, पर तैनात अधिकारियों को उसी दर से पहाड़ और ईंधन भत्ता दिया जायेगा जो 1000 मीटर और उससे अधिक ऊंचाई वाले केन्द्रों पर देय है।

(ख) किसी ऐसे केन्द्र पर, वर्तमान में दिया गया पहाड़ और ईंधन भत्ता समाप्त कर दिया समझा जाएगा, जो ऊपर दिए गए वर्गीकरण में शामिल नहीं हैं।

परन्तु ऐसे अधिकारी के मामले में, जो इस प्रकार के किसी केन्द्र पर 1 मई, 1989 से पहले तैनात था और उस तारीख के बाद भी तैनात रहता है, उसे 30 अप्रैल, 1989 की स्थिति के अनुसार प्रदत्त भत्ता सुरक्षित रखा जाएगा और उस केन्द्र पर उसी वेतनमान में तैनात के समय तक प्रतिमाह अदा किया जाएगा।

8. उक्त विनियमों में, विनियम 24 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात :-

24. चिकित्सा सहायता :-

(1) अधिकारी अपने और अपने परिवार के लिए किए गए वास्तविक चिकित्सा व्यय की निम्नलिखित आधार पर प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगा, अर्थात :-

(क) चिकित्सा व्यय :

फरवरी, 2004 के पहले दिन को और उसके बाद से कोई अधिकारी अपने तथा अपने परिवार के लिए किए गए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति अधिकारी की ओर से दिए गए प्रमाण-पत्र कि उसने यह व्यय किया है और दावा की गई राशि के समर्थन में उसके द्वारा दिए गए विवरण के अनुसार नीचे तालिका में यथाविनिर्दिष्ट सीमा तक पाने का पात्र होगा, अर्थात :-

तालिका

श्रेणी	अधिकतम प्रतिपूर्ति सीमा
कनिष्ठ प्रबन्ध तथा मध्यम प्रबन्ध श्रेणी	3750 रु. अथवा व्यय की गई राशि जो भी कम हो
वरिष्ठ प्रबन्धन तथा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी	5000 रु. अथवा व्यय की गई राशि जो भी कम हो

टिप्पणी :

- (i) उपयोग में न आई चिकित्सा सहायता राशि को अधिकारी संचित कर सकता है परन्तु संचित राशि किसी भी समय ऊपर उल्लिखित अधिकतम राशि के तीन गुने से अधिक नहीं होगी ।
- (ii) चिकित्सा सहायता योजना के अधीन वर्ष 2004 के लिए चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति ग्यारह महीने अर्थात् फरवरी, 2004 से दिसम्बर, 2004 के लिए यथानुपातिक दर से बढ़ाई जाएगी ।

स्पष्टीकरण :

इस विनियम के प्रयोजन के लिए अधिकारी के 'परिवार' का तात्पर्य विनियम 3 के खंड (छ) में यथापरिभाषित परिवार से होगा ।

- (ख) (i) अस्पताल में भर्ती होने के सभी मामलों में अधिकारी के मामले में 100% तक और उसके परिवार के सदस्यों के मामले में 75% तक के अस्पतालीकरण की प्रतिपूर्ति की जाएगी ।
- (ii) 1 मई, 2005 को और इसके बाद से, इस विनियम के अंतर्गत किसी अधिकारी को अस्पतालीकरण व्यय की प्रतिपूर्ति, कर्मकार कर्मचारियों के लिए दिनांक 2 जून, 2005 के द्विपक्षीय समझौते के अंतर्गत निर्धारित अस्पतालीकरण योजना की शर्तों व निबंधनों के अनुसार किंतु नीचे दी गई तालिका में यथा विनिर्दिष्ट सीमाओं तक होगी अर्थात् :-

तालिका

(क)	कनिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड स्केल-I तथा मध्यम प्रबन्ध ग्रेड स्केल - II और III	(i)	शय्या प्रभार स्वयं - 600 रु. प्रतिदिन परिवार - 450 रु. प्रतिदिन
		(ii)	अन्य प्रभार कर्मकार कर्मचारियों पर . लागू अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 125% के स्केल पर
(ख)	वरिष्ठ प्रबन्ध ग्रेड स्केल-IV एवं V तथा शीर्ष कार्यपालक ग्रेड स्केल - VI और VII	(i)	शय्या प्रभार स्वयं - 800 रु. प्रतिदिन परिवार - 600 रु. प्रतिदिन
		(ii)	अन्य प्रभार कर्मकार कर्मचारियों पर लागू अस्पतालीकरण योजना के अंतर्गत निर्धारित सीमाओं के 150% के स्केल पर

(2) उक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि शामिल है) के होते हुए भी और उनका पूर्णतया प्रतिस्थापन करते हुए, नियत तारीख को जो चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) बैंक में उपलब्ध थे, निदेशक-मण्डल उनमें कोई परिवर्तन किए बिना, उन्हें बनाए रखने का विनिश्चय कर सकता है और यदि निदेशक-मण्डल ऐसा तय करता है तो सभी अधिकारी चिकित्सा लाभ (जिसमें अस्पताल में भर्ती आदि भी शामिल है) के लिए नियत तारीख को बैंक में लागू निबंधनों एवं शर्तों के अनुसार ही चिकित्सा खर्च की प्रतिपूर्ति के पात्र होंगे।

(3) चिकित्सा सहायता और अस्पताल में भर्ती की सुविधाएं निलंबनाधीन अधिकारियों को भी दी जाएगी।

9. उक्त विनियमों में, विनियम 25 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

25 : आवास

- (1) कोई भी अधिकारी बैंक द्वारा आवास उपलब्ध कराये जाने के लिए साधिकार हकदार नहीं होगा।
- (2) परन्तु यदि बैंक चाहे तो अधिकारी को आवास उपलब्ध करा सकता है जिसके लिए अधिकारी 1 नवम्बर, 2002 को और उसके बाद से अपने वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 1.75% के बराबर राशि या आवास के लिए मानक किराए का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा।

परन्तु यदि ऐसे आवास पर फर्नीचर भी उपलब्ध कराया गया हो तो अधिकारी से उसके वेतनमान के प्रथम प्रक्रम के 0.4% के बराबर अतिरिक्त राशि बैंक द्वारा वसूल की जाएगी।

परन्तु, जहां बैंक द्वारा यदि ऐसी आवास व्यवस्था उपलब्ध कराई जाती है तो बिजली, पानी, गैस और सफाई प्रभार अधिकारी द्वारा वहन किए जाएंगे।

10. उक्त विनियमों में विनियम 41 में, उप विनियम (I) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- (1) 2 जून, 2005 को तथा इसके बाद से, कोई अधिकारी ड्यूटी पर यात्रा करते समय निम्नलिखित का पात्र होगा, अर्थात् :-

- (i) कनिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी का अधिकारी रेलगाड़ी से प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित 2 टीयर स्लीपर से यात्रा कर सकता है। तथापि, वह विमान (किफायती श्रेणी) से भी यात्रा कर सकता है यदि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबार की आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करने की मंजूरी दी जाए।
- (ii) मध्यम प्रबन्ध श्रेणी का अधिकारी रेलगाड़ी से प्रथम श्रेणी या वातानुकूलित 2 टीयर स्लीपर से यात्रा कर सकता है तथापि, वह विमान (किफायती श्रेणी) से भी यात्रा कर सकता है यदि तय की जाने वाली दूरी 1000 किलोमीटर से अधिक हो परन्तु, वह कम दूरी के लिए भी विमान (किफायती श्रेणी) से भी यात्रा कर सकता है यदि उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा कारोबार की आवश्यकता अथवा सार्वजनिक हित में ऐसा करने की अनुमति दी जाए।
- (iii) वरिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी अथवा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी रेलगाड़ी में वातानुकूलित प्रथम श्रेणी अथवा विमान (किफायती श्रेणी) से यात्रा कर सकते हैं।

- (iv) वरिष्ठ प्रबन्ध श्रेणी अथवा शीर्ष कार्यपालक श्रेणी के अधिकारी, उस स्थानों के बीच कार द्वारा यात्रा कर सकते हैं जो विमान या रेल द्वारा न जुड़े हों, बशर्ते वह दूसरी 500 किलोमीटर से अधिक न हो। परन्तु जब दो स्थानों की बीच की दूरी का अधिकांश भाग विमान या रेल द्वारा तय किया जा सके तो केवल शेष दूरी को सामान्यतः कार द्वारा तय किया जाना चाहिए।
- (v) व्यवसाय की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए अन्य किसी अधिकारी को अपने निजी वाहन द्वारा या टैक्सी द्वारा या बैंक के वाहन द्वारा यात्रा करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राधिकृत किया जा सकता है।

(ख) उप विनियम (4) में खण्ड (क) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित किया जाएगा अर्थात् :-

- (क) **विराम भत्ता :** 1 जून, 2005 को और उसके बाद से अधिकारी नीचे दी गई सारणी में यथाविनिर्दिष्ट 'प्रतिदिन' विराम भत्ता पाने का पात्र होगा :

तालिका

अधिकारियों का वेतनमान/ग्रेड	प्रमुख 'क' श्रेणी के शहर	क्षेत्र I	अन्य स्थान
1	2		
वेतनमान IV और उससे ऊपर के अधिकारी	रु. 600	रु. 550	रु. 500
वेतनमान - I/II/III के अधिकारी	रु. 550	रु. 500	रु. 400

किंतु वेतनमान IV और इससे ऊपर के अधिकारियों के मामले में, चार महानगरों अर्थात् दिल्ली, मुम्बई, कोलकाता और चेन्नई में बाहरी कार्य पर रहते हुए प्रतिदिन देय विराम भत्ता 700/-रु. होगा।

परन्तु, यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 8 घंटे से कम किन्तु 4 घंटे से अधिक है तो ऊपर बताई गई दरों की आधी दर से विराम भत्ता देय होगा।

स्पष्टीकरण :

विराम भत्ते की संगणना के लिए तथा अन्य मामलों में 'प्रतिदिन' का अर्थ है 24 घंटे की अवधि या उसके बाद का कोई भाग, जिसकी गणना विमान यात्रा के मामले में प्रस्थान के लिए रिपोर्टिंग समय और अन्य मामलों में प्रस्थान के नियत समय से लेकर पहुंचने के वास्तविक समय तक की जाएगी। यदि अनुपस्थिति की कुल अवधि 24 घंटे से कम है तो 'प्रतिदिन' का तात्पर्य ऐसी अवधि से है जो 8 घंटे से कम न हो।

11. उक्त विनियमों में विनियम 42 में उप विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

- (3) 1 अप्रैल, 1997 को तथा इस तारीख से स्थानांतरित होने पर अधिकारी पैकिंग, स्थानीय परिवहन तथा सामान के बीमा आदि के संबंध में किए गए खर्चों के लिए नीचे तालिका में दिए गए अनुसार एकमुश्त राशि प्राप्त करने का पात्र होगा :-

तालिका

ग्रेड	एकमुश्त राशि
शीर्ष कार्यपालक तथा वरिष्ठ प्रबन्ध वर्ग	रु. 5000
मध्यम प्रबन्ध वर्ग तथा कनिष्ठ प्रबन्ध वर्ग	रु. 4000

परन्तु यह 1 मई, 2005 को तथा इस तारीख से इस विनियम के प्रावधानों का यह प्रभाव होगा मानो 5000/-रु. और 4000/-रु. के स्थान पर क्रमशः अक्षर शब्द व आंकड़े '8750/- रु.' और '7000/-रु.' रख दिए गए हों।

12. उक्त विनियमों में, विनियम 44 के स्थान पर निम्न विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्

44. छुट्टी यात्रा रियायत :

- (1) चार-वर्षों के प्रत्येक खंड में कोई भी अधिकारी दो वर्ष के प्रत्येक खंड में एक बार अपने गृह नगर की यात्रा के लिए छुट्टी यात्रा रियायत का पात्र होगा अथवा विकल्पतः वह दो वर्षों के एक ब्लाक में अपने गृह नगर तथा दो वर्षों के दूसरे ब्लाक में भारत में किसी भी स्थान की सबसे छोटे मार्ग से यात्रा कर सकता है।
- (2) कोई अधिकारी चार वर्षों अथवा दो वर्षों के खंड के दौरान, जैसा भी मामला हो, अपनी छुट्टी यात्रा रियायत (गृहनगर की यात्रा के अलावा) को छोड़ कर उसका नकदीकरण करा सकता है जिसके लिए जेएमजी वेतनमान-I और एमएमजी वेतनमान-II व III के अधिकारियों के लिए 4500 कि.मी. तक की दूरी (एक ओर का) एसएमजी वेतनमान-IV तथा इससे अधिक अधिकारियों के लिए 5500 कि.मी. (एक ओर) तक की दूरी के लिए वह ट्रेन की जिस श्रेणी से यात्रा करने का पात्र है उसके पात्र किराए के 75% तक की राशि पाने का पात्र है और अपनी छुट्टी यात्रा रियायत के नकदीकरण करवाने का विकल्प चुनते हुए वह अपने लिए और अपने परिवार सदस्यों के लिए उस खण्ड अथवा अवधि जिसमें ऐसा नकदीकरण लिया गया हो, के दौरान केवल एक बार दावा करेगा और छुट्टी किराया रियायत का लाभ उठाते हुए विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा भी छुट्टी किराया रियायत की सुविधा का नकदीकरण कराते समय उपलब्ध होगी।
- (3) किसी अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत लिए जाने की विधि और श्रेणी वही होगी, जिसका स्थानांतरण होने पर यात्रा के मामले में वह सामान्यतः पात्र है और अन्य शर्तें, जिनके अधीन किसी अधिकारी द्वारा छुट्टी यात्रा रियायत ली जाए, समय-समय पर मण्डल द्वारा निश्चित किए अनुसार होगी।
- (4) चार वर्षों में एक बार, जब कोई अधिकारी छुट्टी यात्रा सुविधा का उपयोग करता है तब उसे एक बार में अधिक से अधिक तीस दिनों की अपनी विशेषाधिकार छुट्टी वापस करके इसके नकदीकरण की सुविधा दी जा सकती है अथवा विकल्पतः उसे दो वर्षों के एक खण्ड में अपनी गृह नगर की और दूसरे खण्ड में भारत के किसी भी स्थान की यात्रा करने पर, प्रत्येक खण्ड में अधिकतम 15 दिन की या एक खण्ड में 30 दिनों की विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की सुविधा दी जा सकती है। ऐसे नकदीकरण के प्रयोजन के लिए जिस माह में छुट्टी किराया सुविधा ली जा रही है, उस माह की देय कुल परिलब्धियाँ उसे मिलेंगी।

परन्तु यदि अधिकारी चाहे तो वह एक दिन की अतिरिक्त विशेषाधिकार छुट्टी के नकदीकरण की राशि प्रधानमंत्री राहत कोष के लिए दे सकता है जिसके लिए उसे बैंक को इस आशय का पत्र देते हुए राशि उक्त कोष में प्रेषित करने का प्राधिकार देना होगा।

ओरियन्टल बैंक ऑफ कॉमर्स (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 की अनुसूची**(विनियम 23 का उप विनियम (2) देखें)**

नवम्बर, 2002 के प्रथम दिवस से कोई भी अधिकारी निम्न तालिका में किए गए उल्लेखानुसार विशेष क्षेत्र भत्ता प्राप्त कर सकेगा जब तक कि इन्हें पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से वापिस नहीं लिया जाता

तालिका

क्रमांक	वे स्थान जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		10,000/-रुपये से 14,000/-रुपये तक के वेतन के लिए	14001/-रुपये तथा अधिक के वेतन के लिए
		(रु.)	(रु.)
1.	मिजोरम		
	(क) मिजोरम का चिम्पतीपी जिला एवं मिजोरम में लुंगली जिले में लुंगली नगर से 25 किलोमीटर दूर क्षेत्रों तक	1000	1300
	(ख) मिजोरम के लुंगली नगर से 25 किलोमीटर दूर क्षेत्रों को छोड़कर समूचे लुंगली जिले में	800	1050
	(ग) मिजोरम के समूचे आईजौल जिले में	600	750
2.	नागालैंड	800	1050
3.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह		
	(क) दक्षिण अंडमान (पोर्टब्लेयर सहित)	800	1050
	(ख) उत्तर एवं मध्य अंडमान, लिटल अंडमान, निकोबार एवं नारकोडम द्वीप समूह	1000	1300
4.	सिक्किम	1000	1300
5.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	1000	1300
6.	असम	160	200
7.	मेघालय	160	200
8.	त्रिपुरा		
	(क) त्रिपुरा के दुर्गम क्षेत्र	800	1050
	(ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर समूचे त्रिपुरा में	600	750

क्रमांक	वे स्थान जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		10,000/-रुपये से 14,000/-रुपये तक के वेतन के लिए	14001/-रुपये तथा अधिक के वेतन के लिए
		(रु.)	(रु.)
9.	मणिपुर	600	750
10.	अरुणाचल प्रदेश (क) अरुणाचल प्रदेश के दुर्गम क्षेत्र (ख) दुर्गम क्षेत्रों को छोड़कर समूचे अरुणाचल प्रदेश में	1000 800	1300 1050
11.	जम्मू एवं कश्मीर (1) जिला कठुआ (क) निबबत बनी (ख) लोही (ग) मल्हार (घ) मकोडी (2) (क) जिला ऊधमपुर (i) डुडु बसंतगढ़ (ii) लंडेर भामग इलाका (iii) ठाकराकोट (iv) नगोटे (ख) 2(ग) में सम्मिलित क्षेत्रों को छोड़कर मोहरे तहसील के सभी क्षेत्र (ग) मोहरे तहसील में कम्बन की ओर से गोयल क्षेत्र तक एवं केसी की ओर से अर्नास तक (3) डोडा जिला किश्तवार तहसील में पद्म एवं निवात नौगांव के इलाके	1000 1000 800 1000	1300 1300 1050 1300

क्रमांक	वे स्थान जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		10,000/-रुपये से 14,000/-रुपये तक के वेतन के लिए	14001/-रुपये तथा अधिक के वेतन के लिए
		(रु.)	(रु.)
	4. लेह जिला जिले में सभी स्थान	1000	1300
	5. बारामूला जिला (क) समूचा गुरेज-निरबात, तंगदार उप मंडल एवं केरन इलाका (ख) मच्छल	1000 800	1300 1050
	6. पुंछ एवं राजोरी जिला पुंछ एवं राजोरी व सुन्दरबनी नगरों को छोड़कर पुंछ व राजोरी जिलों के क्षेत्र व दो जिलों में अन्य शहरी क्षेत्र	600	750
	7. वे क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (6) में शामिल नहीं हैं परन्तु वास्तविक नियंत्रण रेखा से 8 कि.मी. तक की दूरी के अंतर्गत हैं अथवा वे क्षेत्र जो राज्य सरकार द्वारा अपने स्टाफ के लिए समय-समय पर सीमा भत्ते के पात्र घोषित किए गए हों ।	600	750
12.	हिमाचल प्रदेश (1) चम्बा जिला 1(क) पंगी तहसील 1(ख) भारमौर तहसील की निम्नलिखित पंचायत एवं गांव (i) पंचायत : बडगांव, बाजोल देयोल कुगती, नयागाम एवं दुन्डाह (ii) गांव : ग्राम पंचायत जगत का घाटू, ग्राम पंचायत चौहाटा के कनारसी 2. उपरोक्त 1(ख) में शामिल गांवों एवं पंचायतों को छोड़कर भारमौर तहसील 3. भटियाट तहसील में झांडरू पंचायत, चूरह तहसील, डलहौजी नगर (बानीखेत मुख्य सहित)	1000 800 600	1300 1050 750

क्रमांक	वे स्थान जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		10,000/-रुपये से 14,000/-रुपये तक के वेतन के लिए (रु.)	14001/-रुपये तथा अधिक के वेतन के लिए (रु.)
	(2) किन्नोर जिला		
	(क) छोटा खम बा ग्राम पंचायतों का, 15/20 क्षेत्र असरंग, चितकुल और हंगोकुनो/चारंग पंचायत ऊपर वर्णित पंचायत क्षेत्र को छोड़करनाथपा और रुपी, पूह उप मण्डल	1000	1300
	(ख) उपरोक्त (क) में शामिल क्षेत्र के अलावा संपूर्ण जिला	600	750
	(3) कुल्लू जिला		
	3(क) खरगा, कुसवार और सरगा की ग्राम पंचायतों को मिलाकर निर्मांड तहसील का 15/20 क्षेत्र	1000	1300
	3(ख) बाहरी सेरज (निर्मंड तहसील में जाकत-खाना एवं बुरों गांवों को छोड़कर) एवं बाहरी जिला (बाहरी सेरज क्षेत्र व पंडरबिस के परगना को छोड़कर परन्तु तहसील निर्मंड के जगत-खाना गांवों एवं बुरों सहित	600	750
	(4) लाहोल एवं स्पीति जिला	1000	1300
	लाहोल एवं स्पीति का सारा क्षेत्र	1000	1300
	(5) शिमला जिला		
	(क) कूट, लबाना-सडाना, सरपारा और चाडी-बरांदा पंचायतों को मिलाकर रामपुर तहसील का 15/20 क्षेत्र	1000	1300
	(ख) दादरा-कवार तहसील, रामपुर में दरकाली की ग्राम पंचायत, कष्ठाठ तहसील एवं मुनीष, परगना सरहन घोपाल तहसील की घोड़ी छैबीस एवं घोड़ीज	800	1050

क्रमांक	वे स्थान जहाँ भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		10,000/-रुपये से 14,000/-रुपये तक के वेतन के लिए	14001/-रुपये तथा अधिक के वेतन के लिए
		(रु.)	(रु.)
	(ग) चोपाल तहसील एवं घोड़ीज, पंजगांव, पात्सनी, परगना सरहान के नौबीस व तीन कौटी टेकलेश क्षेत्र की देउती ग्राम पंचायत, परगना बराबीस, कसबा रामपुर व रामपुर तहसील का परगना रामपुर व घोड़ी नोग, शिमला नगर एवं इसके आसपास के क्षेत्र (धल्ली, जटोग, कसुम्पती, मशोबरा, तारादेवी एवं टूटू)	600	750
	(6) कांगड़ा जिला		
	(क) बार ए भंगल व छोटा भंगल के क्षेत्र	800	1050
	कांगड़ा जिले का धर्मशाला शहर और म्युनिसिपल सीमा से बाहर स्थित निम्नलिखित कार्यालय		
	(ख) कांगड़ा जिला का धर्मशाला नगर व इसकी म्युनिसिपल सीमा से बाहर स्थित परन्तु धर्मशाला नगर में शामिल निम्नलिखित कार्यालय, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, दारी, मिक्ैनिकल वर्कशाप, रामनगर, बाल कल्याण व नगर एवं शहरी योजना कार्यालय सकोह, लोउर सकोह में सीआरएसएफ कार्यालय, कांगड़ा दुग्ध आपूर्ति योजना, दुगिर, हि.रा.प.नि. वर्कशाल सधेर जोनल मलेरिया कार्यालय, दारी, जंगल निगम कार्यालय, शामनगर, चाय फैक्टरी दारी, आईपीएच सब स्टेशन दान, निपटान कार्यालय, शामनगर कार्यालय/जैरसी फार्म, बनौरी रेशम उद्योग कार्यालय, इन्डो जर्मन कृषि वर्कशाप, हि.प्र.लो.नि.वि. मण्डल, लोहना, डीपीओ निगम बुन्दला, विद्युत हि.प्र.रा.वि. मण्डल, घुगगर ।	600	750

क्रमांक	वे स्थान जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		10,000/-रुपये से 14,000/-रुपये तक के वेतन के लिए	14001/-रुपये तथा अधिक के वेतन के लिए
		(रु.)	(रु.)
	(7) मण्डी जिला	1000	1300
	जोगिन्दर नगर तहसील की छुहार घाटी बरगा की तुन्ग तहसील, छेत्री घोटधर गरागुशीह, गाटू, गरयास, जन्जहल्ली, जरमार, जोहर कल्हाननी, कल्वान खोलसाल लोठ, सिलीबागी, सोमांचन, तचधार, ताची दाना की पंचायतें, धर्मपुर ब्लाक की पंचायतें - बिंगा, कमैह, सकलाना, तन्यार एवं ताराखोलह, करसोग तहसील की पंचायतें - बालीधर, बगरा, गोपालपुर, खजोल, महोग, मेहुदी, मंज, पेखी, सेंज, सरहन, सुन्दर नगर तहसील की पंचायत- बोही, बटवारा, धनयारा, पौरा-कोठी, सेरी एवं शोजा		
	(8) सिरमोर जिला	600	750
	(क) बानी, बखाली (पच्छद तहसील) भरोग बेनीहारी (पओंटा तहसील) की पंचायतें बिरला (नहान तहसील) दिब्बर (पच्छड़ तहसील एवं धाना कसोगा (नहान तहसील)		
	(ख) थांसगिरी		
	(9) सोलन जिला	600	750
	मंगल पंचायत		
	(10) हिमाचल प्रदेश के शेष क्षेत्र जो उपरोक्त (1) से (9) में शामिल नहीं हैं।	160	200
13.	उत्तर प्रदेश: चमोली, पिथौरागढ़ एवं उत्तर काशी जिलों के अधीन क्षेत्र	1000	1300
	2 (क) जिले के अन्य क्षेत्र पिथौरागढ़ एवं उत्तरकाशी (उत्तरकाशी के जिला मुख्यालयों सहित)		
	2 (ख) चम्पावत जिला (लोहाघाट के क्षेत्र सहित)		

क्रमांक	वे स्थान जहां भत्ता देय है	देय भत्ते की दरें	
		10,000/-रुपये से 14,000/-रुपये तक के वेतन के लिए	14001/-रुपये तथा अधिक के वेतन के लिए
		(रु.)	(रु.)
14.	उत्तरांचल : रूद्रप्रयाग और चम्पावती जिलों के अंतर्गत क्षेत्र	800	1050

शील कुमार शर्मा, महाप्रबन्धक (मा. सं. वि.)

[विज्ञापन III/4/असा./128/10]

टिप्पणी : मूल विनियम 17 अक्टूबर, 1987 को सरकारी राजपत्र में प्रकाशित हुए थे । तत्पश्चात् किए गए संशोधनों को निम्नलिखित अधिसूचनाओं के द्वारा अधिसूचित किया गया ।

क्रमांक	राजपत्र अधिसूचना सं०	दिनांक
1.	3902	05.11.1987
2.	3904	12.11.1988
3.	3906	04.03.1989
4.	3908	07.10.1989
5.	3910	05.04.1990
6.	3911	09.06.1990
7.	3912	04.05.1991
8.	3913	04.04.1992
9.	3915	09.01.1993
10.	3916	31.12.1994
11.	3919	13.08.1996
12.	3921	30.11.1996
13.	3924	17.04.1999
14.	3925	13.11.1999
15.	3927	19.08.2000
16.	3936	29.09.2001
17.	3940	06.05.2002
18.	3943	08.02.2006
19.	3944	12.02.2007

MINISTRY OF FINANCE
(ORIENTAL BANK OF COMMERCE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st December, 2010

No. 3946 : In exercise of the powers conferred by Section 19 read with sub-section (2) of section 12 of the Banking Companies (Acquisition and transfer of undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of the Oriental Bank of Commerce in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982, namely :-

1. (1) These regulations may be called the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service (Amendment) Regulations, 2010.
- (2) They shall come into force with effect from the 2nd day of June 2005 except wherever stated otherwise in the respective regulations.
2. In the Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982, (hereinafter referred as the said regulations), in regulation 3,
 - (i) for clause (g), the following clause shall be substituted, namely :-

(g) "Family" means the spouse of the officer (who is not an employee of the Bank), wholly dependent unmarried children (including dependent step and legally adopted children) and parents ordinarily residing with and wholly dependent on the officer;
 - (ii) the following clause (o) shall be inserted, namely :-

(o) "Wholly dependent children or parents" mean children or parents having an income not exceeding Rs.2,550/- per month"

Note : If the income of one of the parents exceeds Rs.2,550/- per month or the aggregate income of both the parents exceeds Rs.2,550/- per month, both the parents shall not be considered as wholly dependent on the employee;

3. In the said regulations, in regulation 4, for sub-regulation (4), the following sub-regulations shall be substituted, namely :-

(4) On and from the 1st day of November 2002, the scales of pay specified against each grade shall be as under :-

- (a) Top Executive Grade

Scale – VII – Rs.29340-680/2-30700-900/1-31600-1000/1-32600

Scale – VI – Rs.26620-680/4-29340

- (b) Senior Management Grade

Scale – V – Rs.24140-620/4-26620

Scale – IV – Rs.20480-560/1-21040-620/5-24140

- (c) Middle Management Grade

Scale – III – Rs.18240-560/5-21040-620/2-22280

Scale – II – Rs.13820-500/1-14320-560/10-19920

- (d) Junior Management Grade

Scale – I – Rs.10000-470/6-12820-500/3-14320-560/7-18240

Note : Every officer who is governed by the scales of pay as in force as on 31st October 2002 shall be fitted in the scale of pay set out as in this sub-regulation as on 1st November 2002 on stage to stage basis, i.e. on corresponding stages from first stage onwards in the respective scales and the increments shall fall on the anniversary date as usual except where provided otherwise.

(4A) Nothing in sub-regulations (1), (2), (3) and (4) shall be construed as requiring the Bank to have at all times, officers serving in all these grades.

4. In the said regulations, for regulation 5, the following regulation shall be substituted, namely :-

5, Increments –

- (1) Subject to the provisions of sub-regulation (4) of Regulation 4, on and from 1st day of November 2002, the increments shall be granted subject to the following conditions, namely :-

- (a) The increments specified in the scales of pay set out in sub-regulation (4) of Regulation 4 shall, subject to the sanction of the Competent Authority, accrue on an annual basis and shall be granted on the first day of the month in which these fall due.
- (b) Officers in Scale - I and Scale - II, one year after reaching the maximum in their respective scales, shall be granted further increments including stagnation increment(s) in the next higher scale only as specified in (c) below subject to their crossing the efficiency bar as per guidelines of the Government.
- (c) Officers including those referred to in (b) above who reach the maximum of the Middle Management Grade Scales II and III shall draw stagnation increment(s) for every three completed years of service after reaching the last stage of the Scale II or Scale III as the case may be subject to a maximum of two such increments of Rs.560/- each for officers in the last stage of Scale II and one such increment of Rs.620/- for officers in the last stage of Scale III.

Provided that on and from 1st day of November 1994 the officers in substantive Scale III i.e. those who are recruited in or promoted to Scale III shall be eligible for second stagnation increment three years after having received the first stagnation increment.

Provided further that such increment/s in the next higher scale / stagnation increment/s shall not be allowed to an officer who refuses promotion when offered.

Note : Grant of such increments in the next higher scale shall not amount to promotion. Officers even after receipt of such increments shall continue to get privileges, perquisites, duties, responsibilities or posts of their substantive Scale I or Scale II as the case may be.

- (2) An additional increment each shall be granted in the scale of pay for passing Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers / Junior Associate of Indian Institute of Banking and Finance and Part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination.

Explanation :-

- (a) In the case of an officer who has passed part I or part II of Certified Associate of Indian Institute of Bankers Examination as an officer before the appointed date, the additional increment, or increments as the case may be, shall be given effect to from the appointed date provided that he has not received any increment or received only one increment, for passing both parts of the said Examination.

- (b) On and from 1st day of November, 1987, officers who reach or have reached the maximum in the pay scale and are unable to move further except by way of promotion shall subject to Government guidelines, if any, be granted Professional Qualification Allowance in lieu of additional increments as specified in the Table below :-

TABLE

Those who have passed only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.100 per month after one year of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.100 per month after one year, of which Rs.75 shall rank for superannuation benefits
	(ii)	Rs.250 per month after two years, of which Rs.200/- shall rank for superannuation benefits.

- (c) On and from 1st day of November, 1994, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Allowance shall stand revised as specified in the table below :-

TABLE

Those who have passed only Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.120 per month after one year on reaching top of the scale
	(ii)	Rs.300 per month after two years on reaching top of the scale

Provided that officers who are eligible to draw Fixed personal Allowance in terms of clause (b) of sub-regulation (3) of regulation 5, shall draw Professional Qualification Allowance one year / two years after receipt of such Fixed Personal Allowance respectively for Part I and II as the case may be.

- (d) On and from 1st day of November, 1999, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below :-

TABLE

Those who have passed only Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers and Certified Associate of Indian Institute of Bankers or both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.150 per month after one year on reaching maximum of the scale.
	(ii)	Rs.360 per month after two years on reaching maximum of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

- (e) On and from 1st day of November, 2002, other things being equal, the quantum of Professional Qualification Pay shall stand revised as specified in the table below :-

TABLE

Those who have passed Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Part I of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the scale.
Those who have passed both parts of Certified Associate of Indian Institute of Bankers	(i)	Rs.300 per month after one year on reaching maximum of the scale.
	(ii)	Rs.750 per month after two years on reaching maximum of the scale.

Provided that officers who are in Scale I and Scale II and are granted further increments in the next higher scale as specified in clause (b) of sub-regulation (1) shall draw Professional Qualification Pay after one or two years, as the case may be, on reaching the maximum in such higher scales.

Note :-

- (i) If an officer who is in receipt of Professional Qualification pay is promoted to next higher scale, he shall be granted, on fitment in such higher scale, additional increment(s) for passing Junior Associate of Indian Institute of Bankers / Certified Associate of Indian Institute of Bankers to the extent increments are available in the scale and if no increments are available in the scale, the officer shall be eligible for Professional Qualification Pay in lieu of increment(s).
 - (ii) On and from 1st day of November, 1994, Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay, as the case may be, shall rank for Dearness Allowance, House Rent Allowance and Superannuation Benefits.
 - (iii) an officer shall not be eligible for Professional Qualification Pay as above if he refuses to accept promotion when offered.
 - (iv) If an officer acquiring Junior Associate of Indian Institute of Bankers or Certified Associate of Indian Institute of Bankers (either or both parts) qualifications after reaching the maximum of scale of pay, shall be granted from the date of acquiring such qualification the first installment of Professional Qualification Pay and the release of subsequent installments of Professional Qualification Pay shall be with reference to the date of release of first installment of Professional Qualification Pay.
 - (v) if an officer, as on the 2nd day of June, 2005 has already acquired any of the said qualifications referred to in clause (iv) and has not earned any increment or Professional Qualification Pay on account of acquiring such qualification/s, he shall be, with effect from the 1st day of November, 2002 or the date of acquiring such qualification/s, whichever is later, released Professional Qualification Pay as provided herein above.
- (3) (a) All officers who are in the bank's permanent service as on 1st day of November, 1993 shall get one advance increment in the scale of pay and officers who are on probation on 1st day of November, 1993 will get one advance increment one year after the confirmation.

Note :-

There shall be no change in the date of annual increment because of advance increment.

- (b) An officer who is at the maximum of the scale or who is in receipt of stagnation increment(s) as on 1st day of November, 1993, will draw a Fixed Personal Allowance from 1st day of November, 1993 which shall be equivalent to an amount of last increment drawn plus dearness allowance payable thereon as on 1st day of November, 1993, plus house rent allowance, at such rates as applicable in terms of Regulation 22 and the Fixed Personal Allowance together with House Rent Allowance, if any, as specified in the table below shall remain valid till further revised :-

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.1993 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided.
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
230	5.79	236
250	6.30	257
300	7.56	308
400	10.08	411

- (c) On and from 1st day of November, 1999 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below:-

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.1997 on the increment component	Total Fixed Personal Allowance payable where bank's accommodation is provided.
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
340	4.28	345
380	4.78	385
420	5.29	426
600	7.56	608

- (d) On and from 1st day of November, 2004 other things being equal, the Fixed Personal Pay with House Rent Allowance, if any, shall be as specified in the table below and shall remain frozen for the entire period of service :-

TABLE

Increment Component	Dearness Allowance as on 01.11.2002 on the increment components	Total Fixed Personal Pay payable where bank's accommodation is provided.
(A) Rs.	(B) Rs.	(C) Rs.
560	23	583
620	25	645
680	28	708
1000	41	1041

Note :-

- (i) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay as indicated under column (C) of the tables in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation (5) shall be payable to those officers who are provided with bank's accommodation.
- (ii) Fixed Personal Allowance/Fixed Personal Pay for officers eligible for House Rent Allowance shall be (A) + (B) + House Rent Allowance as indicated in clauses (b), (c) and (d) of sub-regulation (3) of regulation (5) drawn by the concerned officer on the increment component of the relevant scale of pay as specified in sub-regulation (2) and (3) of Regulation 4 is earned.
- (iii) On and from 1st day of November, 1999, there shall be no change in the schedule of release of Professional Qualification Pay as in Explanation (c) of sub-regulation (2) on account of release of Fixed Personal Pay :-

Provided that where any installment of Professional Qualification Pay which on account of the earlier provisions has been shifted by a year and is scheduled for release on or after to 1st day of November, 1999, it shall be released to the officer on and from this date and second installment of Professional Qualification Pay, if any, shall be released on the 1st day of November, 2000.

- (iv) The increment component of Fixed Personal Allowance / Fixed Personal Pay shall rank for superannuation benefits.
- (e) An officer who has earned the advance increment as specified in clause (a) above shall draw the quantum of Fixed Personal Allowance / Fixed Personal Pay as mentioned in clauses (b), (c) or (d) above, one year after reaching the maximum of the scale.

5. In the said regulations, in regulation 21, after sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be inserted, namely :-

(4) On and from the 1st day of November, 2002, Dearness Allowance Scheme shall be as under :-

(a) Dearness Allowance shall be payable for every rise or fall of 4 points over 2288 points in the quarterly average of the All India Average Working Class Consumer Price Index (General) Base 1960 -100.

(b) During the period from the 1st day of November, 2002, to 31st days of January, 2005, dearness allowance shall be payable as per the following rates :-

(i) 0.18% of 'pay' upto Rs.9,650/- plus,

(ii) 0.15% of 'pay' above Rs.9,650/- and upto Rs.15,350/- plus,

(iii) 0.09% of 'pay' above Rs.15,350/- and upto Rs.16,350/- plus,

(iv) 0.04% of 'pay' above Rs.16,350/-

(c) On and from the 1st day of February, 2005, dearness allowance shall be payable at 0.18% of pay.

Note :-

(A) 'Pay' for the purpose of Dearness Allowance shall mean basic pay including Stagnation Increments.

(B) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as specified in Explanations (c), (d) and (e) to sub-regulation (2) of Regulation 5 shall rank for dearness allowance.

6. In the said regulations, for regulation 22, the following regulation shall be substituted, namely :-

22. House Rent Allowance

(1) (a) On and from 1st day of November, 1999, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 2.5% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.

- (b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1st day of November, 1999, the House Rent Allowance as specified in the table below namely :-

TABLE

Where the place of work is in		HRA payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major 'A' Class Cities specified as such from time to time in accordance with the guidelines of the Government & Project Area Centres in Group 'A'	9% of the pay per month
(ii)	Places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	8% of the pay per month
(iii)	Area II i.e. all places not covered by (i) and (ii) above.	7% % of the pay per month

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him shall be the actual rent paid by him for his residential accommodation in excess over 2.5% of the pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or 150% of the House Rent Allowance payable as per Column (2) of the above table, whichever is lower.

- (2) (a) On and from 1st day of November, 2002, where an officer is provided with residential accommodation by the Bank, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less, will be recovered from him.
- (b) Where an officer is not provided any residential accommodation by the Bank he shall be eligible on and from 1st day of November, 2002, the House Rent Allowance as specified in the table below namely :-

TABLE

Where the place of work is in		House Rent Allowance payable shall be
(1)		(2)
(i)	Major 'A' Class Cities & Project Area Centres in Group 'A'	8.5% of Pay
(ii)	Other places in Area I and Project Area Centres in Group 'B'	7.5% of Pay
(iii)	Other places	6.5% % of Pay

Provided that if an officer produces a rent receipt, the House Rent Allowance payable to him / her shall be the actual rent paid by him / her for the residential accommodation in excess over 1.75% of pay in the first stage of the scale of pay in which he / she is placed with a maximum of 150% of the House Rent Allowance payable as per Column (2) of the above table.

- (3) Where an officer resides in his own accommodation, he shall be eligible for a House Rent Allowance on the same basis as mentioned in proviso to clause (b) of sub-regulation (1) and clause (b) of sub-regulation (2) as if he was paying by way of monthly rent a sum equal to one twelfth of the higher of (A) or (B) below :-

(A)

The aggregate of :

- (i) Municipal taxes payable in respect of the accommodation ; and
- (ii) 12% of the Capital cost of the accommodation including the cost of the land and if the accommodation is part of a building, the proportionate share of the capital cost of the land attributable to that accommodation, excluding the cost of special fixtures, like air conditioners; or

(B)

The annual rental value taken for municipal assessment of the accommodation.

Explanation :-

- (1) For the purpose of this Regulation 'standard rent' means:
 - (a) In the case of any accommodation owned by the Bank, the standard rent calculated in accordance with the procedure for such calculation in vogue in the Government.
 - (b) Where accommodation has been hired by the bank, contractual rent payable by the bank or rent calculated in accordance with the procedure in (A) above, whichever is lower.
- (2) "Pay for the purpose of House Rent Allowance shall mean basic pay including stagnation increments.
- (3) Professional Qualification Allowance or Professional Qualification Pay as the case may be, shall rank for House Rent Allowance with effect from the 1st day of November, 1994.
- (4) For the purpose of sub-regulation (1) and (2) of this Regulation and Regulation 23, Area I and Area II shall mean as under :-

Area - I	Places with a population of more than 12 lakhs.
Area - II	All places not included in Area-I.

7. In the said regulations, for regulation 23, the following regulation shall be substituted, namely :-

23. Other Allowances :-

- (1) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the City Compensatory Allowance as specified in the table below, namely :-

TABLE

	Places	Rates
	(1)	(2)
(a)	Places in Area I and in the State of Goa	4% of basic pay subject to a maximum of Rs.540 per month
(b)	Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above,	3% of basic pay subject to a maximum of Rs.375 per month.
(c)	Other places	Nil

- (2) On and from 1st day of November, 2002, the rates of Special Area Allowance shall be as specified in the Schedule to these regulations.
- (3) On and from 1st day of November, 2002, if an officer is serving in an area to be specified as Project Area falling under Group A or Group B, he shall be eligible for a Project Area Compensatory Allowance at the rate of Rs.210/- per month or Rs.185/- per month according to the classification of the area as Group A or Group B.
- (4) On and from the 1st day of January, 2004, if an officer is transferred from one place to another in the midst of an academic year and if he has one or more children studying in school or college, in the former place, he shall be eligible for a mid academic year transfer allowance at the rate of Rs.500/- per month from the date he reports to the later place upto the end of the academic year in respect of all the children studying

Provided that such allowance shall cease if all the children cease studying at the former place.

- (5) On and from the 1st day of June, 2005, if an officer is deputed to serve outside the bank, he may opt to receive the emoluments attached to the post to which he is deputed or he may in addition to his pay, draw a deputation allowance at the rate of 7.75% of pay subject to a maximum Rs.1,500/- per month and such other allowances as he would have drawn had he been posted in the bank's service at that place.

Provided that where he is deputed to an organisation which is located at the same place where he was posted immediately prior to his deputation, he shall receive a deputation allowance equal to 4% of his pay, subject to a maximum Rs.750/- per month.

Provided further that an officer on deputation to the Training Establishment of the bank as a faculty member shall be eligible for deputation allowance at 4% of his pay subject to a maximum Rs.750/- per month.

- (6) If an officer is required to officiate in a post in a higher scale for a continuous period of not less than 7 days at a time or an aggregate of 7 days during a calendar month, he shall receive an officiating allowance equal to 6% of his pay, pro-rata for the period for which he officiates and officiating allowance will rank as pay for purposes of Provident Fund and Pension only.

Provided that where an officer comes to officiate in a higher scale, as a consequence solely of the review of the categorisation of posts under Regulation 6, he shall not be eligible for the Officiating Allowance for a period of one year from the date on which the review of the categorisation takes effect.

- (7) If an officer is posted at a branch where books are closed on the 1st of April and 30th September, a closing allowance of Rs.250/- for each of the two closings.
- (8) On and from 01st day of November, 2002, if the working hours during a day are split with minimum interval of two hours, an officer shall be eligible for a Split Duty Allowance at the rate of Rs.125/- per month.
- (9) If an officer is required to work as custodian of a vault or locker on a holiday, he shall be eligible for a Diem Allowance at the rate to which he is entitled.

- (10) On and from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Hill and Fuel Allowance as specified in the table below, namely :-

TABLE

	Place	Rate
	(1)	(2)
(i)	Place with an altitude of 3000 metres and above	5% of pay subject to a maximum of Rs.1,150 per month
(ii)	Place with an altitude of 1500 metres and above but less than 3000 metres	2.5% of pay subject to a maximum of Rs.500 per month
(iii)	Place with an altitude of 1000 metres and above but less than 1500 metres and Mercara Town	2% of pay subject to a maximum of Rs.400 per month

Note :-

- (a) Officers posted at places with an altitude of not less than 750 metres and which are surrounded by hills with higher altitude which cannot be reached without crossing an altitude of 1000 metres or more shall be paid hill and fuel allowance at the same rate as is payable at centres with an altitude of 1000 metres and above.
- (b) Hill and Fuel allowance presently paid at any centre not covered by the above classification shall stand withdrawn.

Provided that in respect of an officer who was posted in such a centre prior to 1st day of May, 1989, and remains posted at that centre even after that date, the quantum of allowance which he was drawing as on the 30th day of April, 1989 shall be protected and paid to him every month till the time he remains posted at that centre in the same scale of pay."

8. In the said regulations, for regulation 24, the following regulation shall be substituted, namely :-

24. Medical Aid :-

- (1) An officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses actually incurred by him in respect of himself and his family on the following basis, namely :-

(a) Medical Expenses

On and from 1st day of February, 2004, an officer shall be eligible for reimbursement of medical expenses for self and family on the strength of the officer's own certificate of having incurred such expenditure supported by a statement of accounts for the amounts claimed as specified in table below, namely : -

TABLE

Grade	Maximum limit of reimbursement
Junior Management and Middle Management Grade	Rs.3750 or the amount incurred whichever is less
Senior Management and Top Executive Grade	Rs.5000 or the amount incurred whichever is less

Note :-

- (i) An officer may be allowed to accumulate unavailed medical aid so as not to exceed at any time three times the maximum amount provided above.
- (ii) For the year 2004 the reimbursement of medical expenses under the medical aid scheme shall be enhanced proportionately for eleven months i.e. February 2004 to December 2004.

Explanation :-

"Family" of an officer for the purpose of this regulation shall mean the family as defined in clause (g) of regulation 3.

- (b) (i) Hospitalisation charges shall be reimbursed to the extent of 100% in the case of an officer and 75% in the case of his family members in respect of all cases which require hospitalisation.

- (ii) On and from the 1st day of May 2005, reimbursement of hospitalization expenses to an officer under this regulation shall be in accordance with terms & conditions of Hospitalization Scheme laid down under the Bi-partite Settlement dated the 2nd day of June, 2005 for workmen employees, subject to the limits as specified in the table below, namely :-

TABLE

(a)	Junior Management Grade Scale - I and Middle Management Grades Scales - II and III	(i)	Bed Charges Self – Rs.600 per day Family – Rs.450 per day
		(ii)	Other charges – At the scale of 125% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.
(b)	Senior Management Grade Scales – IV and V and Top Executive Grade Scales – VI and VII	(i)	Bed Charges Self – Rs.800/- per day Family – Rs.600/- per day
		(ii)	Other charges – At the scale of 150% of the limits laid down under the Hospitalisation Scheme applicable to workmen employees.

- (2) Notwithstanding the medical benefits (including hospitalization etc.) specified in sub-regulation (1) above and, in complete substitution of the same, the Board may decided to retain in an unaltered form medical benefits (including hospitalization etc.) as available in the Bank on the appointed date and if the Board so decides, all officers shall be eligible for reimbursement of medical expenses only as per the terms & conditions obtaining in the Bank on the appointed date for grant of medical benefits (including hospitalization, etc.)

- (3) Medical Aid and Hospitalisation facilities shall also be admissible to the officers who are placed under suspension.

9. In the said regulations, for regulation 25, the following regulation shall be substituted, namely :-

25. Residential Accommodation

- (1) No officer shall be entitled as of right to be provided with residential accommodation by the Bank.
- (2) It shall, however, be open to the Bank to provide residential accommodation to an officer on payment by the officer, on and from 1st day of November, 2002, a sum equal to 1.75% of the basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed or the standard rent for the accommodation, whichever is less.

Provided that where the officer is provided with furniture at such residence, a further sum equal to 0.4% of basic pay in the first stage of the scale of pay in which he is placed, will be recovered by the Bank from him.

Provided further that, where such residential accommodation is provided by the bank, the charges for electricity, water, gas and conservancy shall be borne by the officer.

10. In the said regulations, in regulation 41, for sub-regulation (1), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

- (1) On and from the 2nd day of June, 2005, an officer shall be eligible for the following while traveling on duty, namely:-
- (i) an officer in Junior Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train. He may, however, travel by air (economy class) if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
 - (ii) an officer in Middle Management Grade is entitled to travel by 1st Class or AC 2-tier Sleeper by train or he may travel by air (economy class) if the distance to be travelled is more than 1000 kms. or for a shorter distance if so permitted by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business or public interest.
 - (iii) an officer in Senior Management or Top Executive Grade is entitled to travel by AC 1st Class by train or by air (economy class).
 - (iv) an officer in Senior Management or Top Executive Grade may travel by car between places not connected by air or rail provided that the distance does not exceed 500 km. and when a major part of the distance between the two places can be covered by air or rail only the rest of the distance should normally be covered by car.

- (v) any other officer may be authorised by the Competent Authority, having regard to the exigencies of business, to travel by his own vehicle or by taxi or by the Bank's vehicle.

(b) in sub-regulation (4), for clause (a), the following clause shall be substituted, namely :-

- (a) **Halting Allowance :-** On and from the 1st day of June, 2005 an officer shall be entitled to 'per diem Halting Allowance as specified in the table below, namely:-

TABLE

Grades / Scales of Officers	Major 'A' Class Cities	Area I	Other Places
1	2		
	Rs.	Rs.	Rs.
Officers in Scale – IV & above	600	550	500
Officers in Scale – I / II / III	550	500	400

Provided that in the case of officers in Scale - IV & above, halting allowance payable per diem while on outstation work at the four metros, viz. Delhi, Mumbai, Kolkata and Chennai, shall be Rs.700/-;

Provided further that where the total period of absence is less than eight hours but more than four hours, Halting Allowance at half the above rates shall be payable.

Explanation :-

For the purpose of computing Halting allowance 'per diem' shall mean each period of twenty four hours or any subsequent part thereof, reckoned from the reporting time for departure in the case of air travel and the scheduled time of departure in other cases, to the actual time of arrival and where the total period of absence is less than twenty four hours 'per diem' shall mean a period of not less than eight hours.'

11. In the said regulations, in regulation 42, for sub-regulation (3), the following sub-regulation shall be substituted, namely :-

- (3) On and from the first day of April, 1997 an officer on transfer shall be eligible to draw a lump sum amount for expenses connected with packing, local transportation, insuring the baggage, etc. as specified in the table below, namely :-

TABLE

Grade	Lump Sum
Top Executive & Senior Management	Rs.5,000
Middle Management & Junior Management	Rs.4,000

48434/10-6

Provided that on and from the first day of May, 2005 the provisions of this sub-regulation shall have effect as if for the letters and figures "Rs.5000" and "Rs.4000", the letters, words and figures "Rs.8750" and "Rs.7000" had been respectively substituted.

12. In the said regulations, for regulation 44, the following regulation shall be substituted, namely :-

44. Leave Travel Concession

- (1) During each block of four years, an officer shall be eligible for leave travel concession for travel to his home town once in each block of two years, or, alternatively, he may travel in one block of two years to his home town and in another block of two years to any place in India by the shortest route.
- (2) An officer, by exercising an option at anytime during a block of four years or two years, as the case may be, may also surrender and encash his Leave Travel Concession (other than travel to home town) upon which he shall be entitled to receive an amount equivalent to 75% of the eligible fare for the class of travel by train to which he is entitled upto a distance of 4500 kms. (one way) for officers in JMG Scale - I and MMG Scale - II & III and 5500 kms (one way) for officers in SMG Scale - IV and above and while opting to encash his Leave Travel Concession shall prefer the claim for himself or herself and his or her family members only once during the block or term in which such encashment is availed off and the facility of encashment of privilege leave while availing of Leave Travel Concession shall also be available while encashing the facility of Leave Travel Concession.
- (3) The mode and class by which an officer may avail of Leave Travel Concession shall be the same as the officer is normally entitled to travel on transfer and other terms and conditions subject to which the Leave Travel Concession may be availed of by an officer shall be as decided by the Board from time-to-time.
- (4) Once in every four years when an officer avails of Leave Travel Concession, he may be permitted to surrender and encash his Privilege Leave not exceeding thirty days at a time or he may whilst travelling in one block of two years to his home town and in other block to any place in India, be permitted encashment of Privilege Leave with a maximum of fifteen days in each block or thirty days in one block and for the purpose of leave encashment all the emoluments payable for the month during which the Leave Travel Concession is availed, shall be admissible.

Provided that an officer at his option shall be permitted to encash one day's additional privilege leave for donation to the Prime Minister's Relief Fund subject to his giving a letter to the Bank to that effect and authorizing the Bank to remit the amount to the Fund.

Schedule to Oriental Bank of Commerce (Officers') Service Regulations, 1982**(See, sub-regulation (2) of regulation 23)**

With effect from the 1st day of November, 2002, an officer shall be eligible for the Special Area Allowance till such time they are withdrawn or modified either wholly or partially, as specified in the Table below, namely :-

TABLE

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	Pay from Rs.14,001/- & above
		(Rs.)	(Rs.)
1.	Mizoram		
	(a) Chimgtuipui District of Mizoram and areas beyond 25 kms. from Lunglei Town in Lunglei District of Mizoram.	1,000	1,300
	(b) Throughout Lunglei District excluding areas beyond 25 kms. from Lunglei town of Mizoram.	800	1050
	(c) Throughout Aizawl District of Mizoram	600	750
2.	Nagaland	800	1,050
3.	Andaman and Nicobar Islands		
	(a) South Andaman (including Port Blair)	800	1,050
	(b) North and Middle Andaman, Little Andaman, Nicobar and Narcondum Islands	1,000	1,300
4.	Sikkim	1,000	1,300
5.	Lakshadweep Islands	1,000	1,300
6.	Assam	160	200
7.	Meghalaya	160	200
8.	Tripura		
	(a) Difficult areas of Tripura	800	1,050
	(b) Throughout Tripura except difficult areas.	600	750

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/- (Rs.)	Pay from Rs.14,001/- & above (Rs.)
9.	Manipur	600	750
10.	Arunachal Pradesh		
	(a) Difficult areas of Arunachal Pradesh	1,000	1,300
	(b) Throughout Arunachal Pradesh except difficult areas.	800	1,050
11.	Jammu and Kashmir		
	(1) Kathua District	1,000	1,300
	(a) Niabat Bani		
	(b) Lohi		
	(c) Malhar		
	(d) Macchodi		
	(2) (a) Udampur District	1,000	1,300
	(i) Dudu Basantgarh		
	(ii) Lander Bhamag Illaqa		
	(iii) Thakrakote		
	(iv) Nagote		
	(b) All areas in Mohre Tehsil other than those included in 2(c).	1,000	1,300
	(c) Areas upto Goel from Kamban Side and areas upto Arnas from Keasi side in Tehsil Mohre.	800	1,050
	(3) Doda District	1,000	1,300
	Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil		

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	Pay from Rs.14,001/- & above
		(Rs.)	(Rs.)
	(4) Leh District All places in the District	1,000	1,300
	(5) Barmulla District		
	(a) Entire Gurez-Nirabat, Tangdar Sub-Division and Keran Illaqa	1,000	1,300
	(b) Matchill	800	1,050
	(6) Poonch and Rajouri District: Areas in Poonch and Rajouri District excluding the towns of Poonch and Rajouri and Sunderbani and other urban areas in the two Districts.	600	750
	(7) Areas not included in (1) to (6) above, but which are within the distance of 8 kms. from the line of Actual Control or at places which may be declared as qualifying for border allowance from time-to-time by the State Government for their own staff.	600	750
12	Himachal Pradesh		
	(1) Chamba District		
	1(a) Pangi Tehsil	1,000	1,300
	1(b) Following Panchayat and Villages of Bharmour Tehsil	800	1,050
	(i) Panchayats : Badgaun, Bajol, Deol Kugti, Nayagam and Tundah		
	(ii) Villages: Ghatu of Gram Panchayat Jagat, Kanarsi of Gram Panchayat Chauhata		
	2. Bharmour Tehsil, excluding Panchayats and Villages included in Part I.b above.		
	3. Jhandru Panchayat in Bhatiyat Tehsil, Churah Tehsil, Dalhousie Town (including Banikhet proper).	600	750

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	Pay from Rs.14,001/- & above
		(Rs.)	(Rs.)
	(2) Kinnaur District :		
	(a) Asrang, Chitkul and HangoKuno/Charang Panchayats, 15/20 Area comprising the Gram Panchayats of Chhota Kham ba, Nathpa and Rup, Pooh Sub-Division, excluding the Panchayat Areas specified above.	1,000	1,300
	(b) Entire District other than Areas included in (a) above	600	750
	(3) Kullu District :		
	3(a) 15/20 Area of Nirmand Tehsil, comprising the Gram Panchayats of Kharga, Kushwar and Sarga	1,000	1,300
	3(b) Outer-Seraj (excluding villages of Jakat-Khana and Burrow in Nirmand Tehsil) and entire District (excluding outer Seraj area and pargana of Pandrabis but including villages JagatKhana and Burrow of Tehsil Nirmand).	600	750
	(4) Lahaul and Spiti District :		
	Entire area of Lahaul and Spiti.	1,000	1,300
	(5) Shimla District :		
	(a) 15/20 area of Rampur Tehsil comprising of Panchayats of Koot, Labana-Sadana, Sarpara and Chad i-Branda.	1,000	1,300
	(b) Dodra-Kawar Tehsil, Gram Panchayat of Darkali in Rampur, Kashapath Tehsil and Munish, Ghor Chaibis of Pargana Sarahan Chopal Tehsil and Ghoris.	800	1,050

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	Pay from Rs.14,001/- & above
		(Rs.)	(Rs.)
	(c) Chopal Tehsil and Ghoris, Panjgaon, Patsnau, Naubis and Teen Koti of Pargana Sarahan, Deothi Gram Panchayat of Taklesh Area, Pargana Barabis, Kasba Rampur and Ghorinog of Pargana Rampur of Rampur Tehsil, Shimla Town and its suburbs (Dhalli, Jatog, Kasumpti, Mashobra, Taradevi and Tutu).	600	750
	(6) Kangra District:		
	(a) Areas of Bar a Bhargal and Chhota Bhargal	800	1,050
	(b) Dharamshala Town of Kangra District and the following offices located outside the Municipal limits but included in Dharamshala Town—Women's ITI, Dari, Mechanical Workshop, Ramnagar, Child Welfare and Town and Country Planning Offices, Sakoh, CRSF Office at lower Sakoh, Kangra Milk Supply Scheme, Dugiar, HRTC Workshop, Sadher, Zonal Malaria Office, Dari, Forest Corporation Office, Sham nagar, Tea Factory, Dari, I.P.H. Sub-Division, Dan, Settlement Office, Sham nagar, Binwa Project, Sham nagar. Office/Jersey Farm, Banuri, Sericulture Office/Indo-German Agriculture Workshop/HPPWD Division. Bundla, Electrical Sub-Division, Lohna, D.P.O. Corporation, Bundla, Electrical HPSEE Division, Ghuggar.	600	750

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/- (Rs.)	Pay from Rs.14,001/- & above (Rs.)
	(7) Mandi District : Chhuhar Valley of Jogindernagar Tehsil, Panchayats in thunag Tehsil-of Bagraa, Chatri, Chhotdhar, Garagushain, Gatoo, Garyas, Janjehli, Jaryar, Johar, Kalhani, Kalwan, Kholanal, Loth, Silibagi, Somachan, Thachdhar, Tachi, Thana, Panchayats of Dharampur Block- Binga, Kamiah, Saklana, Tanyar and Tarakholah, Panchayats of Karsog Tehsil- Balidhar, Bagra, Gopalpur, Khajol, Mahog, Mehudi, Manj, Pekhi, Sainj, Sarahan and Teban, Panchayats of Sundernagar Tehsil- Bohi, Batwara, Dhanyara, Paura- Kothi, Seri and Shoja.	600	750
	(8) Sirmaur District : (a) Panchayats of Bani, Bakhali (Pachhad Tehsil), Bharog Bheneri (Paonta Tehsil), Birla (Nahan Tehsil), Dibber (Pachhad Tehsil) and Thana Kasoga (Nahan Tehsil). (b) Thansgiri Tract	600	750
	(9) Solan District : Mangal Panchayat.	600	750
	(10) Remaining areas of Himachal Pradesh not included in (I) to (9) above.	160	200
13	Uttar Pradesh : Areas under Chamoli, Pithoragarh and Uttar Kashi Districts : 2 (a) Other area of District Pithoragarh and Uttarkashi (including District Headquarters of Uttarkashi). 2 (b) Champawat District (including area of Lohaghat).	1,000	1,300

Serial Number	Places where the allowance is payable	Rates of allowance payable	
		Pay from Rs.10,000/- to Rs.14,000/-	Pay from Rs.14,001/- & above
		(Rs.)	(Rs.)
14	Uttaranchal : Areas under Rudraprayag and Champavat Districts.	800	1,050

SHEEL KUMAR SHARMA, General Manager (HRD)

[ADVT III/4/Exty./128/10]

Note : The principal regulations were published in the official Gazette on the 17th day of October, 1987. The subsequent amendments were notified vide the following notifications :-

S. No.	Gazette Notification No.	Date
1.	3902	05.11.1987
2.	3904	12.11.1988
3.	3906	04.03.1989
4.	3908	07.10.1989
5.	3910	05.04.1990
6.	3911	09.06.1990
7.	3912	04.05.1991
8.	3913	04.04.1992
9.	3915	09.01.1993
10.	3916	31.12.1994
11.	3919	13.08.1996
12.	3921	30.11.1996
13.	3924	17.04.1999
14.	3925	13.11.1999
15.	3927	19.08.2000
16.	3936	29.09.2001
17.	3940	06.05.2002
18.	3943	08.02.2006
19.	3944	12.02.2007